



## जल समाचार

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की ने मनाया 45वां स्थापना दिवस समारोह, राजसं. राजभाषा चल वैजयन्ती शील्ड सतही जल जलविज्ञान प्रभाग ने प्राप्त की

रुड़की: 16.12.2022 को राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा अपना 45वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. कमल किशोर पंत, निदेशक, आई.आई.टी. रुड़की रहे तथा स्थापना समारोह का संचालन डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार सिंह, वैज्ञानिक-डी तथा डॉ. अंजली, वैज्ञानिक-बी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। डॉ. अंजली द्वारा मुख्य अतिथि डॉ. कमल किशोर पंत, निदेशक, आई.आई.टी., रुड़की; संस्थान निदेशक डॉ. सुधीर कुमार तथा स्थापना दिवस समारोह समिति के अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार लोहनी, वैज्ञानिक-जी एवं प्रभागाध्यक्ष को मंच पर आसन ग्रहण करने को आमंत्रित करते हुए स्थापना दिवस समारोह को विधिवत रूप से प्रारम्भ किया गया। समारोह में संस्थान द्वारा रचित जल-स्तुति का गायन संस्थान कार्मिकों के समूह डॉ. एम.के. गोयल, वैज्ञानिक जी, श्री पदम कुमार शर्मा, श्री आशीष कुमार बनर्जी, श्रीमती निशा किचलू, श्रीमती प्रिया गांधी आदि द्वारा

किया गया। गायन उपरांत स्थापना समारोह का विधिवत प्रारम्भ मुख्य अतिथि डॉ. कमल किशोर पंत निदेशक, आई.आई.टी. रुड़की; डॉ. सुधीर कुमार निदेशक, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की; डॉ. अनिल कुमार लोहनी, वैज्ञानिक-जी तथा स्थापना समिति के अध्यक्ष तथा डॉ. पी.के. सिंह वैज्ञानिक-डी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया।

डॉ. अनिल कुमार लोहनी ने संस्थान द्वारा पिछले 45 वर्षों में किए गए कार्यों तथा हासिल की गई मुख्य-मुख्य उपलब्धियों का वीडियो प्रस्तुतिकरण किया तथा पूर्व निदेशक डॉ. एस. रामाशेषन, डॉ. सतीश चन्द्र, डॉ. एस.एम. सेठ, डॉ. के.एस. रामाशास्त्री, डॉ. के.डी. शर्मा, इं. राजदेव सिंह, डॉ. शरद कुमार जैन तथा डॉ. जयवीर त्यागी जी द्वारा संस्थान में दिये गये योगदान, उनके कार्यकाल में पाई गई विशेष उपलब्धियों, के लिए अभिनन्दन एवं साधुवाद दिया।

संस्थान निदेशक डॉ. सुधीर कुमार ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि अत्यन्त हर्ष का अवसर है कि हम राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान का 45वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ एवं सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि विदित है कि इस संस्थान की स्थापना 16 दिसंबर 1978 को भारत सरकार की एक सोसायटी के रूप में

रुड़की में हुई थी एवं तभी से यह संस्थान जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं पर शोध कार्य कर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहा है। आज के समय में यह संस्थान आइएसओ 9001:2015 प्रमाणित संगठन है। इस संस्थान के कार्य के उद्देश्य हैं- “जलविज्ञान के समस्त पहलुओं पर व्यवस्थित और वैज्ञानिक कार्य करना, कार्य निष्पादन में सहायता प्रदान करना, बढ़ावा देना तथा समन्वयन करना; जलविज्ञान के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय, विदेशी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना; सोसाइटी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक शोध और संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना करना, उसका रख-रखाव करना और उसमें पुस्तकें, समीक्षाएं, पत्रिकाएं और अन्य प्रासंगिक प्रकाशन उपलब्ध कराना, तथा जिन उद्देश्यों के लिए संस्थान की स्थापना की गई है, उनकी प्राप्ति के लिए ऐसे अन्य सभी आनुषंगिक, प्रासंगिक या हितकर कार्य करना, जिन्हें सोसायटी आवश्यक समझे।”

आपो हिष्ठा मयोभुवस्था न ऊर्जे दधातन। महे

रणाय चक्षसे।।

-ऋग्वेद

अर्थ-हे जल! आपकी उपस्थिति से वायुमंडल बहुत तरोताजा है और हमें उत्साह और शक्ति प्रदान करता है। आपका शुद्ध सार हमें प्रसन्न करता है, इसके लिए हम आपका आदर देते हैं।

आपने बताया कि संस्थान में 6 वैज्ञानिक प्रभाग हैं तथा 6 क्षेत्रीय केन्द्र जो भिन्न-भिन्न राज्यों में स्थापित हैं। संस्थान मुख्यालय में “सैंटर फॉर क्रायोस्फिपर एंड कलाइमेट चेंज स्टडीज” स्थापित किये जाने हेतु सरकार से अनुमोदन प्रदान हुआ है। संस्थान में 6 प्रयोगशालाएं हैं जो विश्वस्तरीय आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं। संस्थान में एक सैंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडवांस्ड ग्राउंड वाटर रिसर्च भी स्थापित है। संस्थान में भारतीय राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन समिति (INC & CC) का सचिवालय है जो अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है और जलवायु परिवर्तन सत्रों और संगोष्ठियों, विचारगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं आदि के प्रायोजन की समीक्षा करता है। इसके अलावा, संस्थान में यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय जलविज्ञान कार्यक्रम पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (INC-IHP) का सचिवालय भी है। यह संस्थान राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान दे रहा है जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से नदियों को परस्पर जोड़ना, राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल उपलब्धता एवं बेसिन नियोजन, गंगा बेसिनों पर अध्ययन तथा इसके साथ ही विद्युत क्षेत्र, परिवहन, जल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, रक्षा आदि हैं।

**ईशाना वार्याणां क्षयन्तश्रवर्षणीनाम् ।**

**महे रणाय चक्षसे । ।**

**-ऋग्वेद**

हे जल! आपकी दिव्यता कृषि भूमियों में भी संचारित! हे जल, मेरा आग्रह है कि आप फसलों का समुचित पोषण करें।

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान की स्थापना जलविज्ञान तथा जल संसाधन के क्षेत्र में शोध एवं विकास कार्यों के लिए की गई थी। अपनी स्थापना के 45 वर्षों में संस्थान ने राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में उत्कृष्ट योगदान दिया है, परामर्शदात्री परियोजनाओं पर कार्य किया है, विश्वस्तरीय प्रयोगशालाएं विकसित की हैं, अभियंताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा जन साधारण के लिए जन-जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये हैं तथा जलविज्ञान के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर भी विकसित किए हैं। विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित परियोजना (NHP) के माध्यम से राष्ट्रीय



राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान का 45वां स्थापना दिवस।

जलविज्ञान संस्थान राज्य एवं केंद्र सरकार के विभागों के अनेक अभियन्ताओं, वैज्ञानिकों आदि को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है तथा पीडीएस के अन्तर्गत अनेक शोध कार्य भी किये जा रहे हैं। संस्थान द्वारा जलविज्ञानीय अध्ययनों की अनेक प्रायोजित व परामर्शदात्री परियोजना पर उत्कृष्ट शोध कार्य किये जा रहे हैं। मुझे आशा है कि हमारा संस्थान जल संसाधनों के अवरिक्त नियोजन, विकास तथा प्रबन्धन के लिए निरंतर रिसर्च इनपुट प्रदान करने के लिए शतत प्रयासरत रहेगा।

**गंगे व यमुने चैव गोदावरि सरस्वति ।**

**नमदि सिन्धु कावेरि जलेअस्मिन् संनिधं कुरु । ।**

**-ब्रह्मनारदीय पुराण**

हे पवित्र नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु एवं कावेरी, कृपा इस जल में विद्यमान होकर इसे पवित्र कर दो।

डॉ. सुधीर कुमार, निदेशक द्वारा अपने अभिभाषण के अंत में कहा गया कि मैं राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान के समस्त पदाधिकारियों, सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं उनके परिवारों को इस पुनीत अवसर पर पुनः बधाई देता हूँ कि भविष्य में भी हम अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करते हुए अपने संस्थान के गौरव को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर और ऊंचाईयों पर ले जाने में सक्षम होंगे।

मुख्य अतिथि के कर-कमलों द्वारा डॉ. पी.सी. नायक, वैज्ञानिक-एफ, डॉ. एम.एस. राव, वैज्ञानिक-एफ, डॉ. सुरजीत सिंह वैज्ञानिक-एफ, डॉ. अनुपमा शर्मा, वैज्ञानिक-जी आदि वैज्ञानिक/कर्मचारियों को उनके संस्थान में 25 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर उन्हें संस्थान द्वारा दिये जान वाले

मोमेन्टो से सम्मानित किया गया तथा संस्थान में राजभाषा में सर्वाधिक हिन्दी कार्य करने के लिए सतही जलविज्ञान प्रभाग को चल वैजयन्ती शील्ड प्रदान की गई जो डॉ. अनिल कुमार लोहनी वैज्ञानिक-जी एवं प्रभागाध्यक्ष ने प्राप्त की तथा इस वर्ष क्षेत्रीय केंद्रों के लिए शुरू की गई चल वैजयन्ती शील्ड क्षेत्रीय केंद्र जम्मू के अध्यक्ष डॉ. जोस तथा डॉ. एम.के. गोयल, वैज्ञानिक-जी द्वारा प्राप्त की गई।

संस्थान के स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि तथा आई.आई.टी. रुड़की के निदेशक डॉ. कमल किशोर पंत ने अपना मुख्य अतिथि भाषण देते हुए कहा कि वे राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की तथा निदेशक के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने स्थापना दिवस समारोह में उन्हें आमंत्रित किया तथा आपने संस्थान के सभी वैज्ञानिकों तथा कर्मचारियों को संस्थान के 45वें स्थापना दिवस पर बधाई दी। अपने अभिभाषण में अन्य महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हुए उन्होंने निम्न मुद्दों पर विशेष रूप से बात की।

- इंजीनियरिंग व विज्ञान की कोई भी स्त्रीम अकेले कारगर नहीं, जब सभी डिसीप्लीन एक साथ मिलकर समस्याओं के समाधान में भागीदारी में हों तो वह सस्टेनेबल होगी।

- आई.आई.टी. एन.आई.एच. व सी.वी.आर. आई. जैसी संस्थाएं आपस में मिलकर जल व जल से जुड़ी समस्याओं का समाधान परस्पर मिलकर निकाले, यह बहुत उपयोगी कदम होगा।

- उन्होंने कहा कि आज की ज्वलंत समस्या जल, खाद्यान्न व ऊर्जा आधारित हैं और हमें इसके लिए जल का संरक्षण करना होगा।

- कैमीकल वेस्ट बैट्रियों आदि का निराकरण





“जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा” विषय पर आयोजित कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान करते हुए संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. मनोहर अरोड़ा।

प्रबन्धन करने पर विचार किया जाना बहुत जरूरी है ताकि बरसात होने पर उनसे निकलने वाले कैमीकल ग्राउन्ड वाटर में न जा सके।

#### आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम

भारत सरकार देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। जिसके तहत राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये। इसी श्रृंखला में 70वां कार्यक्रम जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा विषय पर आयोजित करने की जिम्मेदारी संस्थान के हिन्दी प्रकोष्ठ को प्रदान की गई। इस कार्यशाला का आयोजन दिनांक 14/7/2021 को खानपुर ब्लॉक के खानपुर गांव, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार में किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्रीमती नुपुर वर्मा, डिप्टी कलक्टर, हरिद्वार तथा डॉ. मनोहर अरोड़ा, डॉ. सोबन सिंह रावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक, श्री अंशुल सिंह, सहायक विकास अधिकारी, समाज कल्याण (विकास खण्ड खानपुर) श्री अम्बरीश कुमार शर्मा, प्रगतिशील किसान एवं समाजसेवी (खानपुर) के कर-कमलों द्वारा किया गया।

सर्व प्रथम कार्यक्रम का संचालन करते हुए राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान की तकनीकी पत्रिका “जल चेतना” के सह-संपादक श्री पवन कुमार ने जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यशाला में आये सभी प्रतिभागियों, कृषकों, मीडिया बन्धुओं, विभिन्न एन.जी.ओ. के प्रतिनिधियों, महिलाओं तथा विकास खण्ड के कर्मचारियों का कार्यशाला में स्वागत किया।

उन्होंने राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत कार्य कर रहा है तथा इसके 6 क्षेत्रीय केन्द्र हैं। राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान का मुख्यालय रुड़की में स्थित है तथा संस्थान द्वारा पूरे देश में अमृत महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं जिसमें जनहित में जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। अमृत महोत्सव श्रृंखला में 70वां कार्यक्रम खानपुर ब्लॉक में आयोजित किया गया जिसमें जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा विषय पर संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न जानकारियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को जल संरक्षण



खानपुर ब्लॉक में आयोजित “जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा” पर आयोजित कार्यशाला के दौरान ब्लॉक परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम।

पैम्फलेट, पोस्टर एवं संस्थान के प्रकाशन/पत्रिकाओं का भी वितरण किया गया।

कार्यशाला में संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. मनोहर अरोड़ा ने “जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा” संबंधी विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि हमें भूजल को संरक्षित रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल उपलब्ध रहे।

हमें ज्यादा से ज्यादा सतही जल का उपयोग करना चाहिए तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल का संरक्षण करना चाहिए। हम सबका दायित्व है कि जल संरक्षण के लिए महिलाओं एवं बच्चों को इसके लिए जागरूक किया जाए।

कृषि वैज्ञानिक डॉ. सोबन सिंह रावत ने कृषि संबंधी कार्यों में किस प्रकार से जल की बचत की जा सकती है इस पर अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया तथा किसानों को टपक सिंचाई, भारत सरकार की सिंचाई योजना तथा कृषि में पानी के प्रबन्धन पर प्रकाश डालते हुए पानी की बचत के उपाय बताये।

मुख्य अतिथि ने राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान द्वारा जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा कहा कि पानी की बचत में महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा होता है उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पानी का कम उपयोग करना चाहिए। जल संरक्षण करने के लिए उन्होंने वहां उपस्थित मुस्कान सहायता समूह तथा बुद्ध स्वयं सहायता समूह एवं अन्य समूहों की महिलाओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि मैं जल संरक्षण

करने वाली महिलाओं को पुरस्कार देने के लिए राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की के पदाधिकारियों से संस्तुति करूंगी।

इस अवसर प्रतिभागियों के लिए “जल संरक्षण” विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया जिसमें प्रतिभागियों ने बड़-चढ़कर हिस्सा लिया तथा जल संरक्षण पर अपने विचार रखे। उन्होंने अपने व्याख्यान में जल संरक्षण से होने वाले फायदों के बारे में बताया।

प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार श्रीमती आशा रानी शर्मा द्वितीय पुरस्कार श्रीमती मेनका तृतीय पुरस्कार श्रीमती बेबी कश्यप एवं सांत्वना पुरस्कार श्री हरि ओम शर्मा ने प्राप्त किया।

इस अवसर पर विकास खण्ड परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें सभी ने बड़-चढ़कर प्रतिभाग किया।

इस कार्यक्रम में खानपुर विकास खण्ड के आस-पास के गांव के किसान, महिलाएं तथा एन.जी.ओ. का संचालन करने वाली महिलाओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा तथा खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती सुमन कोटियाल, श्रीमती मर्यादा, पवन भारती, अम्बरीश कुमार शर्मा, सोनू, रेवानन्द, कोविल, बृजभूषण शर्मा, विपिन, सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित लगभग 100 महिला एवं पुरुष मौजूद रहे। अंत में कार्यक्रम का समापन धन्यवाद प्रस्ताव के साथ किया गया।

**“भारतीय हिमालय में बदलती जलवायु के तहत एकीकृत जल संसाधन निदर्शन” पर प्रशिक्षण कार्यशाला**

स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड को-ऑपरेशन (SDC), नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (NIH), रुड़की में 21 से 24 नवंबर, 2022 को “भारतीय हिमालय में बदलती जलवायु के तहत एकीकृत जल संसाधन निदर्शन” पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को उत्तराखंड में जल संसाधनों के उन्नत आकलन के लिए नवीनतम मॉडलिंग टूल्स पर प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड सरकार के विभिन्न विभागों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण लिया।

भारत और विशेष रूप से हिमालयी राज्यों में सभी के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंध (IWRM) प्रमुख

समाधान है। IWRM पर महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय विशेषज्ञों के एक समूह, जिसमें फ्यूचर वाटर, नीदरलैंड, यूट्रेख्ट विश्वविद्यालय, नेदरलैंड्स, जिनेवा विश्वविद्यालय एवं दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टिट्यूट (TERI), सम्मिलित हैं, को IWRM योजना के विकास हेतु उत्तराखंड, भारत में दीनगड कैचमेंट (डोकरियानी हिमनद को शामिल करते हुए) और भागीरथी नदी बेसिन पर विशिष्ट ध्यान देते हुए हिमनद-जलविज्ञानीय और जल आवंटन मॉडल विकसित करने का दायित्व दिया गया।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हिमालयी क्षेत्र में भारी वर्षा की बढ़ती घटनाओं और हिमनदों के पिघलने के पैटर्न में बदलाव से स्पष्ट हो रहे हैं। बदलते जलवायु मापदंडों के प्रति हिमालय के हिमनदों के पिघलने की प्रतिक्रिया की समझ को बढ़ाना आवश्यक होता जा रहा है। इसलिए शोधकर्ताओं और उपयोगकर्ताओं के बीच उन्नत मॉडलिंग तकनीकों को समझने की क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है। राज्य के सतत विकास की दिशा में एसडीसी के निरंतर प्रयासों के क्रम में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

समापन सत्र के दौरान राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की के निदेशक डॉ. सुधीर कुमार ने इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन की सराहना की और राज्य में जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए ऐसे और कार्यक्रमों की आवश्यकता महसूस की। दिव्या शर्मा, स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड को-ऑपरेशन (एसडीसी) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हिमालयी क्षेत्र में भारी वर्षा की बढ़ती घटनाओं और हिमनदों के पिघलने के पैटर्न में बदलाव से स्पष्ट हो रहे हैं। बदलते जलवायु

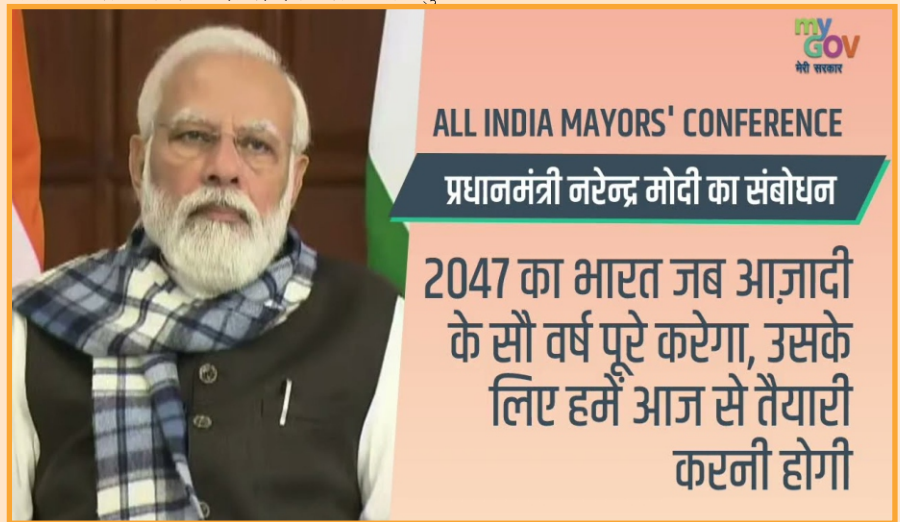
मापदंडों के प्रति हिमालय के हिमनदों के पिघलने की प्रतिक्रिया की समझ को बढ़ाना आवश्यक होता जा रहा है। इसलिए शोधकर्ताओं और उपयोगकर्ताओं के बीच उन्नत मॉडलिंग तकनीकों को समझने की क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है। राज्य के सतत विकास की दिशा में एसडीसी के निरंतर प्रयासों के क्रम में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

इस दौरान डॉ. सुधीर कुमार, दिव्या शर्मा और डॉ. जोहान्स हुनिक, प्रबंधन निदेशक, फ्यूचरवाटर ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और आशा व्यक्त की कि प्रतिभागी प्रशिक्षण कार्यक्रम से मिले ज्ञान को अपने विभागों के नियमित कार्यों में उपयोग करने में सक्षम होंगे।

**जल संरक्षण पर गंभीरता से सोचना होगा : मोदी**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा, ‘देश में शहरीकरण की बढ़ती रफतार के मद्देनजर जल संरक्षण पर ज्यादा गंभीरता से सोचने की जरूरत है। उद्योग और कृषि ऐसे दो प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें पानी की आवश्यकता अधिक है। इन क्षेत्रों को जल संरक्षण अभियान चलाते हुए जनता को जल सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना चाहिए।’ प्रधानमंत्री मोदी ‘वाटर विजन-2047’ के उद्घाटन समारोह को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जल जीवन मिशन को विकास का मानक बताते हुए कहा कि इस दिशा में कई राज्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उल्लेख करते हुए मोदी जी ने कहा कि ‘पर ड्राप मोर क्रॉप’ अभियान के तहत देश में अब तक 70 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में आ चुकी है। सभी राज्यों को इसको बढ़ावा देने की जरूरत है।







जल शक्ति अभियान: कैच द रेन के अंतर्गत अलीगढ़ जिले के ग्राम बरहद, ब्लॉक अकबराबाद में पूनर्जीवित सेंगर नदी (मानसूनी नदी) का अवलोकन करते हुए अधिकारीगण।

जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनसहभागिता बढ़ाने के लिए सामाजिक संगठनों और सिविल सोसाइटी को भी इसमें साथ लेना चाहिए। देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से अब तक 25 हजार अमृत सरोवर बनकर तैयार भी हो चुके हैं। वाटर विजन-2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का महत्वपूर्ण आयाम है। उन्होंने कहा, 'जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है, तो उसे कार्य की गंभीरता भी पता चलती है। इससे जनता में किसी योजना या अभियान के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप भी आती है। जल सुरक्षा के क्षेत्र में भारत अभूतपूर्व कार्य कर रहा है। इसमें निवेश भी खूब बढ़ा है। सरकार ने सर्कुलर इकनामी पर काफी जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रीटेड जल के पुनः उपयोग और ताजा जल को संरक्षित करने से पूरे इकोसिस्टम को बहुत लाभ होता है जिसे आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मनरेगा के तहत जल संरक्षण की दिशा में अधिक से अधिक कार्य करना चाहिए।

जल संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सरकार और संपूर्ण देश के दृष्टिकोण को दोहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों जैसे जल, सिंचाई, कृषि, ग्रामीण व शहरी विकास और आपदा प्रबंधन मंत्रालय के बीच निरंतर संपर्क और संवाद होना चाहिए। अगर इन विभागों के पास एक-दूसरे से संबंधित जानकारी और डाटा होगा तो योजना बनाने में मदद मिलेगी।

### जल शक्ति अभियान: कैच द रेन में राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान ने भी की भागेदारी

जल क्षेत्र में देश की समस्याओं के समाधान एवं भूजल स्तर में वृद्धि हेतु भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में देश के 256 जिलों में जल संरक्षण, वर्षा जल एकत्रीकरण एवं भूजल पुनःपूरण हेतु एक योजना प्रारम्भ की गयी। राष्ट्रीय जल मिशन को इस कार्य हेतु नोडल संस्था बनाया गया।

भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की नोडल संस्था राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा, इस योजना को वर्ष 2022 के लिए "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" के नाम से 29 मार्च 2022 को प्रारम्भ किया गया। योजना के अंतर्गत इस वर्ष ग्राम स्तर तक देश के समस्त जिलों को सम्मिलित किया गया। योजना के अंतर्गत देश के 740 जिले, 7213 ब्लॉक, 2.83 लाख पंचायत एवं 6.62 लाख ग्रामों को सम्मिलित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जल भागीदारी के साथ, राज्यों एवं हितधारकों को जलवायु परिस्थितियों और उप-मृदा स्तर के अनुकूल उपयुक्त वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं को निर्मित करने के लिए प्रेरित करना है।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन योजना के अंतर्गत देश में सतही एवं भूजल की स्थिति में सुधार के लिए पांच क्षेत्रों: (i) जल संरक्षण एवं वर्षा जल एकत्रीकरण (ii) देश में उपलब्ध समस्त जल निकायों की गणना, भू-टैगिंग एवं उन्हें सूचीबद्ध करना तथा

जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजना तैयार करना (iii) सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित करना (iv) सघन वृक्षारोपण तथा (v) जन जागरूकता को चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत चयनित उपरोक्त पांच क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं वर्षा जल एकत्रीकरण सर्वाधिक प्रमुख क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत: इमारतों और परिसरों में निर्मित वर्षा जल एकत्रीकरण तंत्र को निर्मित कर इमारतों और परिसरों की छतों से प्राप्त वर्षा जल का एकत्रीकरण; वर्तमान में उपलब्ध वर्षा जल एकत्रीकरण तंत्र का रखरखाव; नवीन तालाबों चेक डेम का निर्माण; पारंपरिक जल संरक्षण तंत्र का पुनरुद्धार; तालाबों/झीलों एवं उनके जलग्रहण चैनलों से अतिक्रमण को दूर करना; तालाबों की डी-सिल्टिंग; बोरवेल का पुनः उपयोग और पुनर्भरण; जलविभाजक विकास; छोटी नदियों और नालों का पुनरुद्धार; आर्द्रभूमि का पुनरुद्धार और बाढ़-तटों की सुरक्षा; जलग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा; एवं अमृत सरोवरों की प्रगति की जांच सम्मिलित है।

योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में कार्यों की प्रगति के प्रबोधन हेतु एक-एक केंद्रीय जांच दल का गठन किया गया। प्रत्येक जांच दल में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कार्यरत एक अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारी को केंद्रीय नोडल अधिकारी (CNO) के रूप में मनोनीत किया गया। उपरोक्त अधिकारी को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक दल में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के विभिन्न संस्थानों (केन्द्रीय जल आयोग; केंद्रीय भूजल बोर्ड; राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला; केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला) के एक वैज्ञानिक को तकनीकी अधिकारी (TO) चयनित किया गया।

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान के रुड़की स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों में कार्यरत लगभग 30 वैज्ञानिकों को इस कार्य हेतु चयनित किया गया। समस्त वैज्ञानिकों द्वारा पूर्ण दक्षता के साथ अपने कार्यों का निर्वहन कर इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय जल मिशन को सौंप दी गयी।

संपर्क करें:

**पवन कुमार**

सह संपादक "जल चेतना"

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान,

रुड़की।